Need for compilation and publication of data pertaining to tribal people on the official website of the Ministry of Tribal Affairs- laid

श्री राजेन्द्र धेड्या गावित **(**पालघर**):** मैं सरकार का ध्यान एक गंभीर मामले की ओर आर्कषित करना चाहता हूं जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है- हमारे देश में आदिवासी आबादी पर व्यापक डेटा का अभाव। 2011 की जनगणना रिर्पोट के अनुसार, जनजातियां भारत की जनसंख्या का 8.6% हैं। हालांकि, जनजातीय मामलों का मंत्रालय वर्तमान में डेटा के लिए अन्य मंत्रालयों और राज्य सरकारों पर निर्भर है। विभिन्न संकेतकों को शामिल करते हुए एक डेटाबेस स्थापित करना अनिवार्य है, जो सूचित नीति निर्माण, विकास पहल और अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक आधार के रूप में काम करेगा। इसके अलावा, यह विकास कार्यक्रमों की प्रगति और प्रभावशीलता की निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करेगा। मैं जनजातीय मामलों के मंत्रालय से डेटा के संकलन और एक व्यापक डेटाबेस के निर्माण पर विचार करने का अनुरोध करता हूं, जिसे इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जा सके। यह पहल निस्संदेह मौजूदा डेटा की कमी को दूर करने और आदिवासी समुदायों के लिए अधिक प्रभावी और अनुरूप शासन की सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी।